RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

# इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 04 DECEMBER TO 10 DECEMBER 2019 प्रति बुधवार वर्ष 05 अंक 15 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

फ्रेंकफिन को बेस्ट हायर वोकेशनल इंस्टिट्यूट का अवाड

Page 3

सैलरी और सामाजिक दायित्वों में जा रहा है रेलवे का बड़ा फंड: रेलमंत्री

Page 5

Maruti Suzuki की कारें हो रहीं महंगी

Page 7

## editoria!

### सुस्ती का सामना

देश के विकास की रफ्तार में लगातार आ रही कमी चिंता का विषय है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर, 2019 की तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की दर 4.5 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह लगातार छठी तिमाही है, जब जीडीपी के बढ़ने की दर में गिरावट आई है। गौरतलब है कि जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। पिछले कुछ समय से इन तीनों ही क्षेत्रों में भारी सुस्ती दिख रही है। इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी से गिरकर सिर्फ आधा प्रतिशत रह गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो बुरा हाल है जिसमें बढ़ोत्तरी की जगह आधे प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर 4.9 से गिरकर 2.1 फीसदी और सर्विसेज की दर भी 7.3 फीसदी से गिरकर 6.8 ही रह गई है। मुश्किल यह है कि आम उपभोक्ताओं ने हाथ बांध रखे हैं। लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, वे अपने रोजमर्रा के खर्च में कटौती कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मांग पैदा हो नहीं रही है। कारोबारी दुविधा में हैं। कंपनियों को अपना प्रॉडक्शन कम करना पड़ रहा है। उनमें से कई अपने कर्मचारियों की छंटनी करने को मजबूर हो रही हैं। दरअसल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा न होने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्लोडाउन की खबरें आने, आवास प्रॉजेक्ट फंसने, पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियों व बैंकों के संकट में पड़ने और कई वस्तुओं की बढ़ती महंगाई ने लोगों को आशंकाओं से भर दिया है। वे खरीदारी और निवेश से कतरा रहे हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगली तिमाही से हालात सुधर सकते हैं। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पिछले दिनों जो उपाय किए हैं, उनका असर अगली तिमाही से दिखना शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने विदेशी निवेशकों से सरचार्ज हटाया और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की। ऑटो सेक्टर की बेहतरी के लिए घोषणाएं की गईं, संकटग्रस्त रीयल एस्टेट और नॉन बैंकिंग फाइनैंशल कंपनियों के लिए भी कदम उठाए गए। इन सबसे बाजार में सुधार की आशा है। संभव है, बाजार में डिमांड बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक अगले हफ्ते फिर ब्याज दरें घटाए। मगर इन सबके साथ-साथ सरकार को जॉब मार्केट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलनी शुरू हुई तो इससे आम उपभोक्ताओं में विश्वास और उत्साह पैदा होगा। सरकार वक्त की नजाकत समझे। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए वह दलीय भेदभाव भुलाकर सबको साथ ले और कुछ ठोस व कारगर फैसले करे। विपक्ष के लिए भी यह जिम्मेदारी दिखाने का मौका है। सरकार की आलोचना उसका अधिकार है, लेकिन सही मौके पर थोड़ी सकारात्मकता राष्ट्र का संबल बन जाती है।

जीएसटी काउंसिल जल्द लेगा फैसला

# महंगे हो सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, कारें और तंबाकू उत्पाद

**नई दिल्ली। एजेंसी**

गले साल से कारें, तंबाकू और कोला उत्पाद महंगे हो सकते हैं। जीएसटी परिषद की 15 दिसंबर को होने वाली बैठक में इस बात का फैसला लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार को जीएसटी से उतनी आय नहीं हुई, जितना उसने सोचा था। जीएसटी से सरकार को होने वाली आय में लगातार गिरावट हो रही है।

### जीएसटी परिषद ने भेजा राज्यों को पत्र

जीएसटी परिषद ने टैक्स बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा है, जिसमें कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। आरबीआई ने हाल ही में बताया था कि जीएसटी रेट मई 2017 में 14.4 फीसदी था, जो इस वक्त 11.6 फीसदी हो गया।

### इन उत्पादों पर बढ़ सकता है सेस

सरकार ने कमाई बढ़ाने के लिए ऐसे उत्पादों पर सेस लगाने के लिए भी प्रस्ताव दिया, जिनकी बिक्री तो ज्यादा होती है, लेकिन उसका लाभ सरकार को नहीं मिलता है। इन उत्पादों में कारें, कोला और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं।

### इतनी हुई थी जीएसटी से कमाई

नवंबर महीने में जीएसटी के तहत 1.03 लाख करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ था। इसमें केंद्रीय जीएसटी का हिस्सा 19,592 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी 27,144 करोड़ रुपये हिस्सा रहा था। एकीकृत माल और सेवा कर के रूप में 49,028 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। उपकर के रूप में 7,727 करोड़ रुपये मिले। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस बार नवंबर में केंद्रीय जीएसटी से वसूली 19,592 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी से 27,144 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी से 49,028 करोड़ रुपये और जीएसटी उपकर से वसूली 7,727 करोड़ रुपये रही। एकीकृत जीएसटी में से 20,948 करोड़ रुपये आयात से वसूल हुए। इसी तरह उपकर की वसूली में 869 करोड़ रुपये आयातित माल पर उपकर से प्राप्त हुए। इससे पहले सितंबर और अक्तूबर महीने में जीएसटी संग्रह में सालाना आधार पर गिरावट आई थी। बयान में कहा गया कि नवंबर में घरेलू लेन-देन पर जीएसटी संग्रह में 12 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। यह इस साल जीएसटी राजस्व में सबसे अच्छी मासिक वृद्धि है। अक्तूबर महीने में जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ से कम रहा। पिछले महीने की तुलना में यह 5.29 फीसदी कम रहा। अक्तूबर माह में केंद्र व राज्य सरकारों को कुल 95,380 करोड़ का राजस्व जीएसटी से प्राप्त हुआ। यह लगातार तीसरी बार है, जब जीएसटी संग्रह में कमी देखने को मिली है।

### जीएसटी संग्रह में लगातार कमी से एक्शन में सरकार

वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में लगातार कमी को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। सरकार ने इस क्रम में जीएसटी राजस्व संग्रह और प्रशासन में सुधार के वास्ते कदम सुझाने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, 'समिति को व्यापक सुधारों पर विचार करना चाहिए, जिससे सुझावों की एक समग्र सूची सामने आ सकती है।' समिति के विचारार्थ विषयों में दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी बदलाव और स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के उपाय सहित जीएसटी में व्यवस्थित बदलाव के बारे में सुझाव देना शामिल है। इसके अलावा समिति को कर आधार बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों पर सलाह देने के लिए भी कहा गया है। आदेश में कहा गया कि नीतिगत उपाय किए जाने और कानून में बदलाव करने, अनुपालन निगरानी में सुधार और बेहतर डाटा विश्लेषण के इस्तेमाल और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के द्वारा कर चोरी रोकना भी समिति की विषय सूची में शामिल है।

# डेटा संरक्षण विधेयक में उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 15 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

प्रस्तावित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून में बड़ा उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 15 करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार के चार प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस विधेयक को मंजूरी दी है। इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में रखा जा सकता है। एक सूत्र ने कहा, ''व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में किसी बड़े उल्लंघन में कंपनियों पर 15 करोड़ रुपये या उनके वैश्विक कारोबार के चार प्रतिशत (जो भी अधिक हो) तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। उल्लंघन के छोटे मामलों में पांच करोड़ रुपये या वैश्विक कारोबार का दो प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है।'' विधेयक के तहत महत्वपूर्ण डेटा या आंकड़ों को भारत में ही स्टोर करना होगा, जबकि संवेदनशील डेटा का प्रसंस्करण डेटा मालिक की सहमति से देश के बाहर किया जा सकता है। सूत्र ने कहा कि स्वायत्तता से जुड़े मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा या अदालती आदेश की स्थिति में डेटा का प्रसंस्करण बिना सहमति के किया जा सकता है।

# ओपेक देश कच्चे तेल की बढ़ी आपूर्ति को लेकर पशोपेश में

**दुबई। एजेंसी**

आने वाले दिनों में दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति और ज्यादा हो सकती है। इससे ईंधन और ऊर्जा के दाम और नीचे आ सकते हैं। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सदस्य इस स्थिति को लेकर पशोपेश में हैं। ओपेक देश बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर बातचीत के लिये मिलने वाले हैं। ओपेक के तेल उत्पादक देश इस बात पर विचार करेंगे कि पिछले तीन साल से वह जो कटौती कर रहे हैं उस पर टिके रहें या उसमें कुछ कमी लायें अथवा दाम में वृद्धि की उम्मीद में इस कटौती को और ज्यादा किया जाये। यह बातचीत तनाव के बीच हो रही है जिसमें सदस्य देश प्रतिस्पर्धी दिशाओं में बढ़ रहे हैं। सउदी अरब की अरामको के शेयर बाजार में उतरने के बीच सउदी अरब काफी असमंजस की स्थिति में पड़ गया है। वह इस पशोपेश में है कि तेल उत्पादन की कितनी मात्रा से दाम बेहतर स्तर पर होंगे। इसके साथ ही उस पर अरामको के शेयरधारकों का भी अब अतिरिक्त दबाव होगा। हालांकि, ओपेक के कुछ सदस्य देश ऐसे भी हैं जो कि समझौते को नजरअंदाज कर रहे हैं और उन्हें आवंटित मात्रा से अधिक उत्पादन कर रहे हैं।

# एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोने का दाम

**नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

बुधवार को सोने और चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी रही। विदेशों में सोने के दामों में आई तेजी के कारण दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 525 रुपये उछलकर एक महीने के उच्चतम स्तर 39,795 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी दो दिन की नरमी से उबरती हुई 800 रुपये की छलांग लगाकर करीब एक महीने के उच्चतम स्तर 46,400 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गई। विदेशों में सोना मंगलवार को 7 नवंबर के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जिससे आज स्थानीय बाजार खुलते ही इसके दाम चढ़ गये। सोना हाजिर 0.90 डॉलर टूटकर 1,475.25 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। फरवरी का अमेरिकी सोना वायदा 3.20 डॉलर की गिरावट में 1,481.20 डॉलर प्रति औंस रहा। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध पर समझौते में देरी के संकेत से निवेशकों ने सुरक्षित निवेश मानी जाने वाली पीली धातु का रुख किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हो सकता है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह समझौता न हो। इसके बाद सोने में तेजी देखी गयी। अंतराष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर 17.12 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही। स्थानीय बाजार में सोना स्टैंडर्ड 525 रुपये की बढ़त के साथ 05 नवंबर के बाद के उच्चतम स्तर 39,795 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। सोना बिटुर भी इतनी ही तेजी के साथ 39,625 रुपये प्रति दस ग्राम पर रहा। आठ ग्राम वाली गिन्नी 100 रुपये की बढ़त में 30,300 रुपये पर पहुंच गयी। चांदी हाजिर 800 रुपये चमककर 46,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गयी जो 07 नवंबर के बाद का उच्चतम स्तर है। चांदी वायदा भी 800 रुपये उछलकर 44,950 रुपये प्रति किलोग्राम बोली गयी। सिक्का लिवाली और बिकवाली 10-10 रुपये की बढ़त के साथ क्रमशः 920 रुपये और 930 रुपये प्रति इकाई पर पहुंच गये।

# इकॉनमी को राहत, एसऐंडपी ने 'स्थिर परिदृश्य' के साथ भारत की रेटिंग को बरकरार रखा

**नई दिल्ली। एजेंसी**

अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच कुछ रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग घटाए जाने के बीच एसऐंडपी के रुख से सरकार को राहत मिली है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसऐंडपी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को 'स्थिर परिदृश्य' के साथ 'बीबीबी' पर बरकरार रखा है। आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एसऐंडपी की यह रेटिंग इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि कुछ सप्ताह पहले ही एक अन्य वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के रेटिंग परिदृश्य को 'स्थिर' से 'नकारात्मक' कर दिया था। अर्थव्यवस्था दीर्घावधि वृद्धि हासिल करती रहेगी

चक्रवर्ती ने ट्वीट किया, 'एसऐंडपी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ 'बीबीबी' पर कायम रखा है। एजेंसी का कहना है कि हालिया गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर प्रभावशाली दीर्घावधि वृद्धि दर हासिल करती रहेगी। बीबीबी रेटिंग किसी इकाई की अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता को दर्शाती है। हालांकि, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों या बदलती परिस्थितियों से उसकी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है।

### साढ़े छह साल के निचले स्तर पर जीडीपी ग्रोथ रेट

एसऐंडपी की ताजा रेटिंग ऐसे समय आई है, जब विपक्ष अर्थव्यवस्था में आती गिरावट को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि सरकार आर्थिक वृद्धि दर में आती गिरावट को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई है, जो इसका छह साल का निचला स्तर है।

### इकॉनमी में सुस्ती चक्रीय

वित्त मंत्रालय ने एसऐंडपी द्वारा भारत पर जारी संक्षिप्त प्रकाशन का हवाला देते हुए कहा, 'हालिया गिरावट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घावधि में प्रभावशाली वृद्धि दर हासिल करती रहेगी। ऐसा समझा जाता है कि मौजूदा आर्थिक सुस्ती संरचनात्मक कारणों से होने के बजाय चक्रीय अधिक है।'

### बेहतर प्रदर्शन का अनुमान

एसऐंडपी का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी और अगले दो साल के दौरान वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी। एजेंसी ने भारत के मामले में स्थिर परिदृश्य इस आधार पर बनाए रखा है कि अगले दो साल के दौरान आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी और भारत की बाह्य स्थिति भी बेहतर रहेगी। इसके साथ ही राजकोषीय घाटा ऊंचा रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर यह अनुमानों के दायरे में बना रहेगा।

# फूड सेफ्टी लाइसेंस के रिन्यूअल से मिल सकती है छूट

**नई दिल्ली। एजेंसी**

***कारोबारियों को अब फूड सेफ्टी लाइसेंस हर साल रिन्यू कराने से जल्द निजात मिल सकती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) लाइसेंसिंग की वन-टाइम फीस और नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रहा है, जिसकी सिफारिश पर सरकार बदलावों को वैधानिक जामा पहनाएगी। सैंपल फेल होने की सूरत में मैन्युफैक्चरर के बजाय ट्रेडर्स पर कार्रवाई के मामलों में भी नियम और साफ हो सकते हैं।***

अथॉरिटी के शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को व्यापार संगठनों के साथ एक बैठक के दौरान यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया, 'फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) की कारोबारी सुगमता के लिए कानून में व्यापक बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल जिन चीजों पर सहमति बनती दिख रही है, उनमें हर साल लाइसेंस रिन्यू कराने के बजाय वन टाइम फीस का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग में मैन्युअल दखल पूरी तरह खत्म होगा।' लंबी अवधि के लिए फीस चुकाकर रजिस्ट्रेशन या स्टेट लाइसेंस ले चुके करोबारी अगर टर्नओवर या किसी अन्य बदलाव के चलते सेंट्रल लाइसेंसिग के दायरे में आते हैं तो नई लाइसेंस फीस में पहले चुकाई गई रकम भी एडजस्ट हो सकती है। फिलहाल 12 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले हर खाद्य कारोबारी को रजिस्ट्रेशन लेना होता है, जिसकी फीस मामूली होती है, लेकिन 12 लाख से 20 करोड़ रुपये टर्नओवर पर स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी सालाना फीस 2000 रुपये है, जबकि इससे ज्यादा टर्नओवर, इंटरस्टेट या इंटरनेशनल ट्रेड सहित कई मामलों में सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है, जिसकी सालाना फीस 7500 रुपये है। छोटे कारोबारी जहां लाइसेंस फीस और सालाना रिन्यूअल के चलते इससे दूरी बनाते रहे हैं, वहीं अपग्रेडेशन के समय मौजूदा लाइसेंस पर चुकाई गई फीस लैप्स होने का भी विरोध होता रहा है।

ब्रांडेड और पैकेज्ड आइटमों में गड़बड़ी या सैंपल फेल होने ट्रेडर के खिलाफ केस की शिकायतों पर अधिकारियों ने कहा कि अगर ट्रेडर के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि उसने अपनी तरफ से कोई टेंपरिंग नहीं की है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के सेक्रेटरी जनरल वी के बंसल ने बताया कि ऐसे मामले बढ़े हैं, जब बड़ी कंपनियों के पूरी तरह से सील्ड फूड ब्रांड में ग्राहक को कोई खामी मिली या दुकान से उठाया गया सैंपल फेल हो गया तो फूड सेफ्टी एक्ट के तहत मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पहले उस ट्रेडर पर ही केस दर्ज कर लिया जाता है। इस बारे में कानूनी अमेंडमेंट के साथ नियम साफ होने चाहिए। बैठक में ट्रेडर्स की ओर से यह मांग भी रखी गई कि चूंकि जीएसटी की थ्रेशहोल्ड लिमिट 40 लाख हो गई है, ऐसे में फूड सेफ्टी लाइसेंस की अनिवार्यता की सीमा भी इसके बराबर की जाए।

# नीतिगत दर पर रिजर्वबैंक के निर्णय से पहले घरेलू शेयर बाजार मजबूत

**मुंबई। एजेंसी**

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दर घटाने के अनुमान से स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को अंतिम समय में बैंकिंग, वाहन और चुनिंदा आईटी कंपनियों में लिवाली तेज हो गयी थी और प्रमुख सूचकांक शुरुआती गिरावट से उबर कर लाभ में बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 174.84 अंक यानी 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 40,850.29 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 40,886.87-40,475.83 अंक के दायरे में रहा। सेंसेक्स की 20 कंपनियां के शेयर लाभ में रहे। एनएसई का निफ्टी भी 43.10 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 12,037.30 अंक पर बंद हुआ। एनएसई की 50 में से 34 कंपनियों में तेजी रही। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा मोटर्स का शेयर सर्वाधिक 7.1 प्रतिशत की बढ़त में रहा। इसका कारण प्रीमियम हैचबैक वाहन पेश करने की घोषणा करना रहा। येस बैंक में करीब छह प्रतिशत, आईसीआईसीआई बैंक में चार प्रतिशत और भारतीय स्टेट बैंक में 1.7 प्रतिशत की तेजी रही। वेदांता लिमिटेड, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, ओएनजीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी लाभ में रहे। हालांकि एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो में गिरावट रही। कोटक सिक्योरिटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष इक्विटी टेक्निकल रिसर्च श्रीकांत चौहान ने कहा, "वैश्विक एवं घरेलू बाजारों से सकारात्मक तथा मिश्रित संकेतों के मिलने से बाजार में उथल-पुथल रही। शुरुआत में भारत बांड ईटीएफ ने बाजार पर कुछ दबाव डाला, लेकिन कारोबार के आखिर के कुछ घंटों में अमेरिका से व्यापार शुल्क को लेकर आयी सकारात्मक खबरों ने बाजार की मदद की।" आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के अध्यक्ष इक्विटी रिसर्च पारस बोथरा ने कहा कि बाजार को रिजर्वबैंक के द्वारा बृहस्पतिवार को नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत से अधिक की कटौती का अनुमान है। बीएसई के समूहों में धातु कंपनियों में सर्वाधिक 1.66 प्रतिशत की तेजी रही। इसके बाद बैंकेक्स और आईटी का स्थान रहा। पूंजीगत वस्तुओं में सर्वाधिक गिरावट रही। अमेरिका और चीन की व्यापार वार्ता के उलझने से निवेशकों में घबराहट का माहौल रहा, इसके कारण एशियाई बाजारों में गिरावट रही। जापान का निक्की 1.05 प्रतिशत, हांग कांग का हैंग सेंग 1.25 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.73 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.23 प्रतिशत की गिरावट में रहा। यूरोपीय बाजार शुरू में बढ़त में चल रहे थे।

# लंदन, हांगकांग में नियुक्त होंगे सीमा शुल्क खुफिया अधिकारी

**नयी दिल्ली।** सरकार लंदन, हांगकांग, दुबई और ब्रसेल्स में सीमाशुल्क खुफिया अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्य अधिकारियों की तलाश में है। विदेशों में इन अधिकारियों की नियुक्ति का मकसद व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने तीन स्थानों के लिए विदेश में सीमाशुल्क खुफिया नेटवर्क (कॉइन) अधिकारी चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डीआरआई सीमाशुल्क धोखाधड़ियों और तस्करी पर नजर रखने वाली शीर्ष एजेंसी है। उन्होंने बताया कि दुबई और हांगकांग में इन अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय वाणिज्यदूतावास में वाणिज्य दूत के तौर पर की जाएगी। वहीं लंदन और ब्रसेल्स के भारतीय उच्चायोग में इनकी नियुक्ति प्रथम सचिव के तौर पर की जाएगी। यह पहली दफा नहीं है जब लंदन या अन्य स्थानों पर कॉइन अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने बीजिंग दूतावास और गुआंगझोऊ के भारतीय वाणिज्य दूतावास में कॉइन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इससे पहले नेपाल, सिंगापुर और अमेरिका समेत कई अन्य देशों में कॉइन अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

अधिकारियों ने बताया कि कॉइन अधिकारी विदेशों में घटित होने वाले व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय धोखाधड़ी मामलों की जांच में अहम भूमिका अदा करते हैं। इन अधिकारियों का चयन एक समिति करेगी जिसमें विदेश मंत्रालय से भी सहमति ली जाएगी। इन्हें अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति देगी। इस नियुक्ति में रुचि रखने वाले अधिकारी बृहस्पतिवार तक आवेदन कर सकते हैं। उनकी वार्षिक प्रदर्शन रपट को इसके लिए प्रमुख तरजीह दी जाएगी। जिन अधिकारियों के पास डीआरआई, प्रवर्तन निदेशालय, मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) और सीमा शुल्क (रोकथाम) में काम करने का अनुभव है, वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

# नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक

## पिछले साल के 197,637 करोड़ के मुकाबले 6% की बढ़ोतरी

**नई दिल्ली। एजेंसी**

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कलेक्शन नवंबर में 6 पर्सेंट बढ़कर 1.03 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले के दो महीनों में उएऊ कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई थी। फेस्टिव सीजन में शॉपिंग और कम्प्लायंस बेहतर होने का पिछले महीने कलेक्शन बढ़ने में बड़ा योगदान हो सकता है। पिछले वर्ष नवंबर में उएऊ कलेक्शन 97,637 करोड़ रुपये और इस वर्ष अक्टूबर में 95,380 करोड़ रुपये रहा था।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि GST कलेक्शन में बढ़ोतरी इकनॉमी में रिवाइवल का संकेत है। इससे डिमांड में बढ़ोतरी का भी पता चल रहा है। सरकार ने एक बयान में कहा, 'दो महीने की नेगेटिव ग्रोथ के बाद नवंबर में उएऊ रेवेन्यू में अच्छा सुधार हुआ है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पर GST कलेक्शन 12 पर्सेंट बढ़ा है, जो वर्ष से दौरान सबसे अधिक है।' मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में इकनॉमिक ग्रोथ धीमी होने के कारण टैक्स रेवेन्यू पर दबाव रहा है। अप्रैल-अक्टूबर में नेट टैक्स रेवेन्यू 3.4 पर्सेंट बढ़ा है। टैक्स कलेक्शन में वृद्धि से सरकार को फिस्कल मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी।

जुलाई-सितंबर में देश की इकनॉमिक ग्रोथ 4.5 पर्सेंट के साथ छह वर्ष के निचले स्तर पर रही थी। सितंबर और अक्टूबर में उएऊ कलेक्शन पिछले वर्ष के समान महीनों की तुलना में क्रमशः 2.7 पर्सेंट और 5.3 पर्सेंट गिरा था। ईय में पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा, 'कलेक्शन में बढ़ोतरी उत्साह बढ़ाने वाली है, लकिन एक महीने के कलेक्शन को एक बड़ा संकेत मानना गलत होगा क्योंकि अक्टूबर त्योहारों का भी महीना था। हमें ट्रेंड को देखना होगा।'

IDFC फर्स्ट बैंक के चीफ इकनॉमिस्ट इंद्रनील के अनुसार, 'GDP आंकड़ों से भी व्यक्तिगत खपत पर खर्च बढ़ने का संकेत मिल रहा है। इस वजह से यह उम्मीद है कि उएऊ कलेक्शन में अब बढ़ोतरी हो सकती है।'

कम्प्लायंस के उपाय बढ़ने से भी कलेक्शन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। EY के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा, 'एनालिटिक्स के जरिए स्क्रूटनी बढ़ने जैसे उपायों से कम्प्लायंस में बढ़ोतरी हुई है।' नवंबर में सेंट्रल GST कलेक्शन 19,592 करोड़ रुपये, स्टेट उएऊ 27,144 करोड़ रुपये और इंटीग्रेटेड GST 49,028 करोड़ रुपये (इम्पोर्ट पर कलेक्ट किए गए 20,948 करोड़ रुपये सहित) रहा। अक्टूबर के लिए 30 नवंबर तक दाखिल GSTR 3B रिटर्न की संख्या 77.83 लाख थी।

बयान में कहा गया कि आयात पर जीएसटी संग्रह में नवंबर में 13 प्रतिशत की गिरावट रही। अक्टूबर में आयात से होने वाले जीएसटी संग्रह में 20 प्रतिशत की गिरावट आई थी। सरकार ने नियमित समायोजन के तहत एकीकृत जीएसटी से केंद्रीय जीएसटी में 25,150 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी में 17,431 करोड़ रुपये समायोजित किये। नियमित समायोजन के बाद नवंबर महीने में कुल राजस्व संग्रह केंद्रीय जीएसटी के लिये 44,742 करोड़ रुपये तथा राज्य जीएसटी के लिये 44,576 करोड़ रुपये रहा।

## फ्रेंकफिन को बेस्ट हायर वोकेशनल इंस्टिट्यूट का अवार्ड

**इंदौर। आईपीटी नेटवर्क**

फ्रेंकफिन इंस्टिट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को बेस्ट हायर वोकेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट 2019 का अवॉर्ड हासिल हुआ है। स्किलिंग इंडिया समिट एंड अवार्ड्सः स्ट्रेंग्थिंग स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी 'इवेंट में लगातार चौथी बार, नई दिल्ली के होटल शांगरी-ला में आयोजित किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री माननीय श्री राज कुमार सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। फ्रेंकफिन ग्रुप के फाउंडर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमेन श्री के.एस. कोहली ने पुरस्कार प्राप्त किया। भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रिन्योरिशप के यूनियन मिनिस्टर डॉ. महेंद्र नाथ पांडे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

## फिच / लोन ग्रोथ के लिए बैंकों को 2020-21 तक 50000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजीकरण की जरूरत

**नई दिल्ली। एजेंसी**

देश के बैंकों को लोन ग्रोथ और एनपीए से उबरने के लिए अगले वित्त वर्ष (2020-21) तक 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को ये आउटलुक जारी किया। फिच का कहना है कि रिकवरी में कमी और प्रोविजनिंग में इजाफे से जूझ रहे बैंकिंग सेक्टर के लिए अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। एजेंसी ने भारतीय बैंकों के लिए निगेटिव आउटलुक बरकरार रखा है। फिच का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार बैंकों को जो पूंजी देगी वह रेग्युलेटरी जरूरतें पूरी करने, प्रोविजनिंग और 10 सरकारी बैंकों के मर्जर का खर्च वहन करने में ही चली जाएगी। नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों, रिएल एस्टेट और एसएमई की दिक्कतों का समाधान नहीं हुआ तो एनपीए रेश्यो में सुधार जारी रखना मुश्किल होगा। बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर भी दबाव रह सकता है, क्योंकि फ्लोटिंग रेट वाले लोन बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने का दबाव है।

## पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को मिली मंजूरी यूजर्स का डाटा हो जाएगा और सुरक्षित

**नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्शन बनल को मंजूरी दे दी है। अब सरकार संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में इसके लिए विधेयक पेश करेगी। हालांकि, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बिल को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि इस बिल की चर्चा पहले संसद में की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने विधेयक को कैबिनेट और दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास भेज दिया है। उन्होंने हाल ही में उच्च हाउस को सूचित किया है कि डाटा प्रोटेक्शन लॉ पर काम जारी है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। नए बिल से भारत की MNCs पर पड़ेगा प्रभावः इस नए कानून का भारत की MNCs पर डाटा लोकलाइजेशन आवश्यकताओं और क्रॉस-बॉर्डर डाटा ट्रांसफर प्रतिबंधों को लेकर काफी प्रभाव पड़ सकता है। यूरोपयन यूनियन के जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR) की तरह सरकार ने पिछले साल एक व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा पेश किया था जो सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डाटा के उपयोग को रेग्यूलेट करेगा। इस ड्राफ्ट बिल को द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018 के नाम से पेश किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.एन. श्री कृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह ने तैयार किया था। अब पर्सनल डाटा के कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए नियम बनाए जाएंगे जिसमें यूजर की सहमति, पेनाल्टी और क्षतिपूर्ति जैसी चीजें शामिल होंगी। पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार जल्द ही बैलेंस्ड पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ पेश करेगी। साथ ही यह भी कहा कि भारत कभी भी डाटा को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा।

## एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर खत्म किया चार्ज

**मुंबई। आईपीटी नेटवर्क**

डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने कार्ड के जरिये उसे किए जाने वाले सभी भुगतान पर सुविधा शुल्क को समाप्त कर दिया है। यह शुल्क छूट एक दिसंबर से प्रभावी हो गई है। एलआईसी ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड के जरिये प्रीमियम नवीकरण, नए प्रीमियम या ऋण अथवा पॉलिसियों पर लिए गए कर्ज के ब्याज के भुगतान पर एक दिसंबर से कोई अतिरिक्त शुल्क या सुविधा शुल्क नहीं लगेगा। एलआईसी ने कहा कि क्रेडिट कार्ड के जरिये निःशुल्क लेनदेन की यह सुविधा सभी संग्रहण प्रणालियों-कार्ड रहित भुगतान और कार्ड डिप-सेल्स मशीनों पर स्वाइप पॉइंट पर उपलब्ध होगी। जीवन बीमा बाजार में एलआईसी की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है। कंपनी के ग्राहक आनलाइन लेनदेन के माईलिक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।

# निवेशकों को खूब लुभा रहा Ujjivan Small Finance Bank का आईपीओ, अब तक मिला 160 गुना अभिदान

**नई दिल्ली। एजेंसी**

खुदरा निवेशकों ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) में जबरदस्त रुचि दिखाई है। कंपनी के आईपीओ को बुधवार को शाम चार बजे तक 164.20 गुना अधिक का अभिदान मिल चुका है। कंपनी के आईपीओ के लिए बोली लगाने की आज आखिरी तारीख थी। कंपनी ने 750 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। कंपनी के आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन की शुरुआत सोमवार को हुई थी। कंपनी ने 36-37 रुपये प्रति शेयर की दर तय कर रखी थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस आईपीओ से प्राप्त अधिकतर राशि का इस्तेमाल टीयर-1 शहरों में अपनी पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ का लॉट साइज 400 शेयरों का था। इसका मतलब है कि इस आईपीओ के आवेदन के लिए कम-से-कम 14,800 रुपये की जरूरत थी। खुदरा निवेशकों के लिए अधिकतम निवेश की सीमा दो लाख रुपये थी। इस आईपीओ को दूसरे दिन 4.86 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला था। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से जारी बयान के मुताबिक कंपनी ने एंकर इंवेस्टर्स के जरिए 303.75 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी के एंकर इंवेस्टर बीडिंग में सिंगापुर सरकार, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सुंदरम म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल जैसी कंपनियों ने हिस्सा लिया। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इस ऑफर को मैनेज कर रहे हैं। माइक्रो-फाइनेंस कंपनी Ujjivan Financial Services ner Ujjivan Small Finance Bank की होल्डिंग कंपनी है। इस आईपीओ के बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी घटकर 84% हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के मुताबिक अगले दो साल में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी को घटाकर 40 फीसद पर लाना है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों का आबंटन नौ दिसंबर, 2019 को पूरा होने एवं बीएसई एवं एनएसई पर 12 दिसंबर, 2019 को लिस्टिंग की संभावना है। बैंक की उपस्थिति 24 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में है और 30 सितंबर, 2019 तक इसके ग्राहकों की संख्या 49.4 लाख थी।

## हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार Sensex में 175 अंकों की बढ़त

**मुंबई। आईपीटी नेटवर्क**

बुधवार को गिरावट के साथ कारोबार करने के बाद शाम में बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 174.84 अंकों की तेजी के साथ 40,850.29 और निफ्टी 43.10 अंकों की बढ़त के साथ 12,037.30 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तेजी नजर आई। अमेरिका और चीन की व्यापार वार्ता को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से एशियाई बाजारों में तेज गिरावट आने का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी नजर आया। बुधवार को शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 25 अंकों की गिरावट के साथ 40,650.31 और निफ्टी 6.60 अंक लुढ़ककर 11,987.60 - 6.60 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे कल बृहस्पतिवार को घोषित होने वाले हैं। निवेशक इसके पहले सतर्कता बरतते नजर आए। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन के साथ व्यापार सौदा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद होने का अनुमान जाहिर करने से निवेशक परेशान रहे। मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के बाद लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसक्स 126 अंकों की गिरावट के साथ 40,675.45 और निफ्टी 54 अंक लुढ़ककर 11,994.20 के स्तर पर बंद हुआ। कल बैंकिंग, ऑटो, मेटल और फार्मा के शेयरों में गिरावट नजर आई।

# गोल्डमैन सैक्स ने भी घटाकर 5.3% किया GDP ग्रोथ का अनुमान

**मुंबई। एजेंसी**

ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है। हालांकि कंपनी ने अगले साल इक्विटी सूचकांक में 8.5 प्रतिशत वृद्धि की संभावना जताई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 5.3 प्रतिशत रह सकती है जबकि पूर्व में इसके 6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया था।

पिछले सप्ताह दूसरी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के आंकड़े आने के बाद ब्रोकरेज कंपनी ने अनुमान कम किया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही जो 26 तिमाही का न्यूनतम स्तर है। इससे पहले जापान की नोमुरा ने आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाते हुए 2019-20 में इसके 4.9 प्रतिशत रहने की संभावना जताई।

गोल्डमैन सैक्स की मुख्य अर्थशास्त्री प्राची मिश्रा ने कहा कि आर्थिक वृद्धि बहुत नीचे आ गई है और यहां से इसमें सुधार की उम्मीद है। इसमें उम्मीद की तुलना में तेजी से सुधार की संभावना है। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत बेहतर वैश्विक आर्थिक स्थिति, एनबीएफसी समस्या से संबद्ध घरेलू वित्तीय संकट के कमजोर होने, सकारात्मक राजकोषीय उपायों से वृद्धि में तेजी की उम्मीद है। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय में काम कर चुकी मिश्रा ने कहा कि आर्थिक स्थिरीकरण के शुरूआती संकेत है।

उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये बृहस्पतिवार को नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। हालांकि मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने को देखते हुए आने वाले समय में रीपो दर में कटौती पर विराम लगा सकता है। ब्रोकरेज कंपनी ने यह भी कहा कि घाटा एफआरबीएम (राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन कानून) कानून के लक्ष्य से ऊपर जा सकता है और यह 2019-20 में 3.6 प्रतिशत रह सकता है।

मिश्रा ने कहा कि पहले भी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से कई बार चूक हुआ है और जीएसटी जैसे सुधारों को देखते हुए इसे अधिक प्रतिकूल रूप से नहीं देखा जा सकता। ब्रोकरेज कंपनी ने यह भी कहा कि वृहत और कंपनियों की कमाई के आधार पर इक्विटी सूचकांक में लगभग 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकता है। निफ्टी अभी 12,000 के आसपास है और 2020 के अंत में यह 13,000 अंक तक जा सकता है।

# पैन की जगह आधार नंबर दे रहे हैं? गलत नंबर डाला तो लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना

**नई दिल्ली। एजेंसी**

आधार नंबर की जगह परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का इस्तेमाल करते वक्त आपको काफी सतर्कता बरतनी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पैन-आधार इंटरचेंजिबियलिटी से संबंधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। आधार की जगह पैन नंबर देते वक्त सावधानी बरतने का कारण यह है कि अगर आपने गलत पैन या आधार नंबर डाल दिया तो आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। यही नहीं, आप फॉर्म में जितनी जगह यह गलती करेंगे आपका जुर्माना उतना ही बढ़ता जाएगा और हर गलती के लिए यह 10,000 रुपये होगा। मतलब अगर आपने पांच जगह पर पैन या आधार नंबर गलत दिया है तो आपको प्रति गलती 10,000 के हिसाब से 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

केंद्र सरकार ने बजट 2019 में आयकर अधिनियम के सेक्शन 272ॅ में संशोधन किया है। इसलिए, करदाताओं को पैन नंबर या आधार नंबर या पैन की जगह आधार नंबर डालते वक्त बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आयकर अधिनियम के सेक्शन 272B के तहत अगर किसी व्यक्ति द्वारा भरा गया पैन नंबर या आधार नंबर गलत पाया जाता है तो असेसिंग

ऑफिसर 10,000 रुपये का जुर्माना करेगा और जितनी बार यह गलती होगी जुर्माना भी उतनी ही बार लगेगा।

आयकर अधिनियम का सेक्शन 272B यह भी कहता है कि किसी डॉक्युमेंट्स में सेक्शन 139A के सबसेक्शन (6A) में अगर करदाता को पैन या आधार नंबर देने की जरूरत है और अगर सब-सेक्शन के प्रावधानों के आधार पर नंबर गलत पाया जाता है तो असेसिंग ऑफिसर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और जितनी जगह गलती की गई है, जुर्माना उतना ही गुना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन वाधवा कहते हैं, 'आयकर अधिनियम के सेक्शन 272B के अनुसार, किसी व्यक्ति को सेक्शन 139(5)(c) के तहत किसी भी डॉक्युमेंट में व्यक्ति द्वारा पैन या आधार नंबर देना है और अगर वह नंबर गलत डाला जाता है या उसे लगता है कि नंबर गलत हो सकता है तो असेसी ऑफिसर उसपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। बजट 2019 में इस सेक्शन में संशोधन कर 'प्रत्येक' शब्द को जोड़ा गया है। अब आप जितनी बार गलत पैन या आधार नंबर डालेंगे हर एक गलती के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा।'

इसलिए, इस तरह की गलती से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप जो आधार या पैन नंबर डालने जा रहे हैं और अच्छी तरह चेक कर लें। जमा किए गए डॉक्युमेंट्स का एक रेकॉर्ड अपने पास भी रखें, ताकि बाद में इस बात का सबूत रहे कि आपने सही नंबर डाला था।

# भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती

## वैश्विक कार्बन उत्सर्जन बढ़ने की गति धीमी पड़ी

**लंदन। एजेंसी**

वैश्विक कार्बन उत्सर्जन बढ़ने की रफ्तार बीते वर्ष की तुलना में 2019 में धीमी हुई है और चीन और भारत में कोयला इस्तेमाल में इजाफे की रफ्तार में सुस्ती आने समेत कई कारक इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। यह अनुसंधान 'नेचर क्लाइमेट चेंज' जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन जलाने और भूमि इस्तेमाल में बदलाव जैसी मानवजनित गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड के कुल उत्सर्जन के 2019 में 43 अरब टन तक पहुंचने की संभावना है। अध्ययन में शामिल ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर के अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि 2019 में भारत से होने वाले उत्सर्जन में 1.8 फीसदी की वृद्धि का अनुमान जताया गया है जो वर्ष 2018 के मुकाबले खासा कम है और इसकी वजह कमजोर आर्थिक वृद्धि है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में खासी धीमी हो गई है जिससे कोयला तथा तेल की खपत और सीमेंट का उत्पादन प्रभावित हुआ है। उनके अनुसार भारी बारिश होने से कोयला उत्पादन और उसके उपभोग में कमी आई क्योंकि भारी बारिश के कारण कोयला खदानों में पानी भर गया जबकि पनबिजली उत्पादन बढ़ा है। अनुसंधान के मुताबिक कोयला जलाने से होने वाला उत्सर्जन 2018 की तुलना में 0.9 फीसदी घट सकता है।दूसरी ओर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल बढ़ने से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में 2019 में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि हो सकती है वह भी तब जबकि कोयला उपभोग घटा है। ऐसे में कई देशों ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने जीवाश्म ईंधन रुझान के संबंध में अपने सालाना विश्लेषण में कहा कि कार्बन उत्सर्जन इस वर्ष 0.6 फीसदी बढ़ सकता है जो पिछले वर्ष के मुकाबले तो कम है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के हिसाब से अभी भी बहुत अधिक है। कार्बन बजट रिपोर्ट के एक लेखक कोरिन ले केरे ने कहा, ''तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल निश्चित ही बढ़ रहा है। प्राकृतिक गैस उत्सर्जन में वृद्धि का सबसे बड़ा भागीदार है।

## ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देने के मामले में सात स्थान उछलकर 73वें पायदान पर पहुंचा भारत

**संयुक्तराष्ट्र। एजेंसी**

ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देने की किसी अर्थव्यवस्था की तैयारी के सूचकांक में भारत छह स्थान की छलांग लगाकर 73वें स्थान पर पहुंच गया। व्यापार एवं विकास पर संयुक्तराष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) के कारोबार-से-उपभोक्ता (बीटूसी) ई-वाणिज्य सूचकांक 2019 में 152 देशों के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग तैयार की गयी है। नीदरलैंड लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। इस सूचकांक के शीर्ष 10 स्थानों में आठ पर यूरोपीय देश काबिज हैं। शीर्ष दस में यूरोप से बाहर के देशों में सिंगापुर तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 10वें स्थान पर है। भारत इस साल सूचकांक में 73वें स्थान पर रहा। भारत वर्ष 2018 में 80वें और 2017 में 83वें स्थान पर रहा था। भारत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में ईरान 42वें, कजाखस्तान 57वें, अजरबैजान 62वें, वियतनाम 64वें और ट्यूनिशिया 70वें स्थान पर रहा। सूचकांक में स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद सिंगापुर, फिनलैंड, ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का स्थान रहा।

## डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की बढ़त के साथ बंद

**मुंबई। आईपीटी नेटवर्क**

अमेरिका - चीन व्यापार समझौते की खबरों के बीच निवेशकों की धारणा सुधरने से रुपया बुधवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 13 पैसे बढ़कर 71.53 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। मुद्रा कारोबारियों मे कहा कि बाजार प्रतिभागियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक बृहस्पतिवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में नीतिगत दर में कटौती करने का फैसला ले सकता है। इसके अलावा , विदेशी पूंजी के निरंतर निवेश से भी रुपये को मजबूती मिली। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया गिरावट के साथ 71.76 रुपये डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान , यह ऊंचे में 71.53 रुपये और नीचे में 71.81 रुपये प्रति डॉलर तक गया। अंत में रुपया मंगलवार के बंद से 13 पैसे की तेजी के साथ 71.53 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। स्थानीय मुद्रा मंगलवार को 71.66 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

## लद्दाख में वाहनों के पंजीयन के लिये सरकार ने पेश किया नया पंजीयन टैग 'एलए'

**नयी दिल्ली। एजेंसी**

लद्दाख में वाहनों के पंजीयन के लिये सरकार ने एक नये पंजीयन टैग 'एलए' की शुरुआत की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ''केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा 12 जून 1989 को प्रकाशित अधिसूचना एसओ-444(ई) में संशोधन किया है। इसके तहत क्रम संख्या 17 में बदलाव लाते हुए इसमें क्रम संख्या 17ए के तहत लद्दाख एलए को जोड़ा गया है।'' सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो नये केंद्रशासित प्रदेश का गठन किया है। लद्दाख में कारगिल और लेह दो जिले हैं तथा यह अब दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है।

# 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की पहल 1 जून 2020 से हो जाएगी शुरू

**नई दिल्ली। एजेंसी**

केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि आने वाले एक जून से देश में 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' (वन नेशन, वन राशन कार्ड) की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। यह व्यवस्था बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों और अत्यंत गरीब लोगों को कवर करेगी। इस पहल के माध्यम से योग्य लाभार्थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक राशन कार्ड का उपयोग करते हुए देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना खाद्यान्न ले सकेंगे। उपभोक्ता मामलों, खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने लोकसभा में बताया कि यह सुविधा ई-पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक या आधार सत्यापन के बाद ही उपलब्ध होगी। एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) पहल के तहत अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा केवल पूरी तरह से ऑनलाइन ई-पीओएस मशीन वाली उचित मूल्य की दुकान पर ही उपलब्ध होगी। पासवान ने कहा है कि यह पहल पूरे देश में एक जून से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गणेश सिंह और कुछ अन्य मेंबर्स द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी है। पासवान ने कहा कि फिलहाल राशन कार्ड के लिए 14 राज्यों में पॉश मशीन की सुविधा शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह सुविधा आरंभ हो जाएगी। साथ ही उन्होंने लोकसभा में बताया कि सरकार का यह लक्ष्य है कि अगले साल एक जून तक 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की पहल आरंभ हो जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

# भारत में 2020 में औसतन 9.2 पर्सेंट बढ़ सकती है सैलरी: रिपोर्ट

**नई दिल्ली।** अगले साल भारत में कर्मचारियों की सैलरी एशिया में सर्वाधिक 9.2 पर्सेंट बढ़ सकती है। हालांकि इस खुशी को 'महंगाई डायन' काफी हद तक कम कर देगी और महंगाई दर को अजस्ट करने के बाद वास्तविक वृद्धि 5 पर्सेंट ही रह जाएगी। सोमवार को सामने आई एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। कॉर्न फैरी ग्लोबल सैलरी फोरकास्ट के मुताबिक, भारत में कर्मचारियों की सैलरी औसतन 9.2 पर्सेंट बढ़ सकती है, लेकिन महंगाई दर को समाहित करने के बाद यह वृद्धि करीब आधी रह जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशिया में भारत सर्वाधिक वेतन वृद्धि वाले देश के रूप में उभरा है। कॉर्न फैरी इंडिया के चैयरमैन और रीजनल मैनेजिंग डायरेक्टर नवनीत सिंह ने कहा, 'दुनिया में मेहनताना में गिरावट के बावजूद भारत में तेज वृद्धि दिख रही है। मौजूदा आर्थिक परिदृश्य और सरकार के रिफॉर्म्स के बीच अधिक वेतन वृद्धि की आशा बनी हुई है।' अनुमान के मुताबिक, 2020 में वैश्विक रूप से सैलरी 4.9 पर्सेंट बढ़ेगी, जबकि 2.8 पर्सेंट अनुमानित महंगाई दर के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि 2.1 फीसदी रह जाएगी। 2020 में एशिया में सर्वाधिक सैलरी ग्रोथ की दर 5.3 फीसदी रहने का अनुमान है। रियल वेज सैलरी की बात करें तो 2.2 फीसदी के इन्फ्लेशन रेट के साथ समाहित करने के बाद वह 3.1 फीसदी रहेगी। कॉर्न फेरी इंडिया के असोसिएट क्लाइंट पार्टनर रूपक चौधरी ने कहा, 'भारत में 2020 में औसत सैलरी ग्रोथ 9.2 पर्सेंट रहने का अनुमान है, और लो इन्फ्लेशन

के साथ असल सैलरी ग्रोथ 5.1 फीसदी रहेगी, जो विश्व में सबसे ज्यादा सैलरी ग्रोथ में शामिल होगी।' अन्य एशियाई देशों की बात करें तो इन्डोनेशिया के लिए यह सैलरी ग्रोथ का औसत 8.1 फीसदी, मलयेशिया, चीन और कोरिया के लिए क्रमशः 5%. 6% और 4.1 फीसदी रहने का अनुमान है। जापान और में यह दर सबसे कम (2%) रहने रका अनुमान है, जबकि 3.9% के औसत के साथ ताइवान का नंबर जापान के बाद है।

## सरकार ने स्वतंत्र निदेशकों का डेटा बैंक शुरू किया

**नयी दिल्ली।** सरकार ने स्वतंत्र निदेशकों के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए सोमवार को स्वतंत्र निदेशकों का डेटा बैंक शुरू किया। इसमें मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों के साथ ही स्वतंत्र निदेशकों के लिए पात्र लोगों का एक ' व्यापक डेटा बैंक' होगा, जहां उसने जुड़ी जानकारियां मौजूद होंगी। कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों के मुताबिक , सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए यह जरूरी होगा कि वह एक दिसंबर, 2019 से तीन महीने के भीतर डेटा बैंक में अपना पंजीकरण करा लें। मंत्रालय ने आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, 'वे कंपनियां भी डेटा बैंक में अपना पंजीकरण करा सकती हैं, जो सही कौशल रखने वाले व्यक्तियों को तलाशने , चुनने और उनसे जुड़ना चाहती हैं , ताकि उन व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जा सके।' डेटा बैंक पोर्टल का रखरखाव भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) करेगा। स्वतंत्र निदेशकों को खुद के मूल्यांकन के लिए एक परीक्षा देना भी जरुरी होगा। यह परीक्षा मार्च 2020 के शुरू से उपलब्ध होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि डेटा बैंक को 'www.mca.gov.in' और 'www.independentdirectorsdatabank.in' पर देखा जा सकता है।

# सैलरी और सामाजिक दायित्वों में जा रहा है रेलवे का बड़ा फंड: रेलमंत्री

**नई दिल्ली। एजेंसी**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे की कमाई 10 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रेलवे का परिचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेशियो) वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जिसका मतलब यह है कि रेलवे को 100 रुपये कमाई के लिए 98.44 रुपये खर्च करने पड़े हैं। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इसके लिए सातवें वेतन आयोग की वजह से सैलरी और पेंशन पर बढ़े खर्च और सामाजिक दायित्वों के बोझ को जिम्मेदार बताया है। रेलमंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में दिए लिखित जवाब

में कहा कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद से रेलवे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर 22 हजार करोड़ रुपये अधिक खर्च कर रहा है, जिससे वित्तीय स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। गोयल ने यह भी कहा कि नई लाइनों के निर्माण और सामाजिक दायित्वों के तहत अलाभकारी इलाकों में भी ट्रेन चलाने में भी इसके फंड का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है।खर्च का रेलवे पर असर प्रश्नकाल में रेलमंत्री ने कहा, '7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से रेलवे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर 22 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। ऑपरेटिंग लॉस में इसका योगदान है।' मंत्री ने कहा कि रेलवे साफ-सफाई, उपनगरीय ट्रेन चालने और गेज बदलाव पर भी काफी खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा, 'इन सबका खर्च है और इसका रेलवे पर असर पड़ता है।'

### 'सामाजिक दायित्व और लाभकारी सेक्टर के लिए अलग हो बजट'

गोयल ने कहा, 'जब हम पूरे पिक्चर को देखते हैं, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना और सामाजिक दायित्व के तहत ट्रेनों को चलाने से ऑपरेटिंग रेशियो एक साल में 15 पर्सेंट नीचे चला जाता है।' रेलमंत्री ने कहा, 'समय आ गया है कि हम सामाजिक दायित्वों पर खर्च और लाभकारी सेक्टर्स के लिए बजट को अलग करने की संभावना तलाशें।'

### कैग रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

ऑपरेटिंग रेशियो के आंकड़े से रेलवे की हालत समझना बेहद आसान है और सीधा सा अर्थ है कि अपने तमाम संसाधनों पर रेलवे को 2 फीसदी की भी कमाई नहीं हो पा रही है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेल का परिचालन अनुपात वित्त वर्ष 2017-18 में 98.44 प्रतिशत रहने का मुख्य कारण पिछले वर्ष 7.63 प्रतिशत संचालन व्यय की तुलना में उच्च वृद्धि दर का 10.29 प्रतिशत होना है। इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2008-09 में रेलवे का परिचालन अनुपात 90.48 प्रतिशत था, जो 2009-10 में 95.28 प्रतिशत, 2010-11 में 94.59 प्रतिशत, 2011-12 में 94.85 प्रतिशत, 2012-13 में 90.19 प्रतिशत, 2013-14 में 93.6 प्रतिशत, 2014-15 में 91.25 प्रतिशत, 2015-16 में 90.49 प्रतिशत, 2016-17 में 96.5 प्रतिशत तथा 2017-18 में 98.44 प्रतिशत दर्ज किया गया।

# निष्काम कर्म से मिलती है मुक्ति

**गीता के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण ने यह बताया है कि सभी कार्यों को पूर्णता के साथ करना चाहिए। योग के माध्यम से प्रभु के साथ एकरूप हो कर जो अपने सभी कार्यों को एकाग्रता के साथ करता है और किसी फल की चाह नहीं रखता, वही सही अर्थों में निष्काम योगी है।**

गीता जयंती (8 दिसंबर) पर विशेष

स्वामी विवेकानंद

जिस समय सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया गया था, उस समय दो सम्प्रदायों में बड़ा वाद-विवाद चल रहा था। इनमें से एक सम्प्रदाय वैदिक यज्ञों, पशुबलि तथा इसी प्रकार के अन्यान्य कर्मों को ही धर्म का सार-सर्वस्व समझता था। दूसरा यह मानता था कि असंख्य अश्वों एवं पशुओं का वध धर्म नहीं कहा जा सकता। इस दूसरे सम्प्रदाय में अधिकतर ज्ञानमार्गी तथा संन्यासी थे। उनका विश्वास था कि समस्त कर्मों का त्याग और आत्मज्ञान की उपलब्धि ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। गीता के प्रणेता कृष्ण ने निष्काम कर्म के अपने महान सिद्धांत को प्रतिपादित कर इन दोनों विरोधी दलों के विवाद को शांत कर दिया।

अनेक लोगों का यह मत है कि गीता महाभारत के समय नहीं लिखी गई, वरन् बाद में उसमें जोड़ दी गई। यह बात ठीक नहीं है। गीता के जो विशिष्ट सिद्धांत हैं, वे महाभारत के प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं, और यदि गीता को बाद में जोड़ी हुई मान कर निकाल दिया जाए, तो महाभारत के प्रत्येक भाग में से वे अंश निकालने पड़ेंगे, जिनमें गीता के सिद्धांत पाए जाते हैं।

निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? आजकल बहुत से लोग इसका अर्थ यह समझते हैं कि कर्म इस प्रकार किया जाए, जिससे मन को हर्ष-विषाद स्पर्श न कर सके। यदि यही निष्काम कर्म का सच्चा अर्थ हो, तो पशुओं को निष्काम कर्मी कहा जा सकता है। कुछ पशु अपने बच्चों को ही निगल जाते हैं और ऐसा करने में उन्हें कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता। डाकू अन्य लोगों का सब माल छीन कर उनका सर्वनाश कर देते हैं, और यदि वे पर्याप्त कठोर होकर दुख-सुख की परवाह न करें, तो उन्हें भी फिर निष्काम कर्मी कहना पड़ेगा। दीवार को सुख-दुख का अनुभव नहीं होता, पत्थर में सुख-दुख की भावना नहीं होती, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वे निष्काम कर्मी हैं। यदि निष्काम कर्म उपर्युक्त अर्थ में प्रयुक्त किया जाए, तब तो वह दुष्टों के हाथों में एक प्रबल अस्त्र बन जाएगा। वे तरह-तरह के बुरे कर्म करते जाएंगे और कहेंगे कि हम तो बिना किसी कामना के ये सब काम कर रहे हैं। इसलिए यदि निष्काम कर्म का अर्थ यही हो, तो हम कहेंगे कि गीता में एक बड़े भयानक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अतः यह अर्थ निश्चित रूप से नहीं हो सकता। फिर, यदि हम गीता के उपदेश से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन को देखें, तो वह भिन्न ही प्रकार का मालूम होगा। अर्जुन ने युद्ध में भीष्म और द्रोण का संहार किया। साथ ही उसने अपनी इच्छाओं, स्वार्थ एवं निम्न प्रकृति का भी लाखों बार बलिदान किया।

गीता कर्मयोग की शिक्षा देती है। हमें योग (एकाग्रता) के द्वारा कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के कर्मयोग में हमें क्षुद्र अहंभाव की चेतना नहीं रह जाती। जब योगयुक्त होकर कार्य किया जाता है, तब -मैं यह-वह कर रहा हूं- यह ध्यान ही नहीं रहता। पाश्चात्यों की समझ में यह बात नहीं आती। वे कहते हैं कि यदि अहंभाव न रहे, यदि अहं का नाश हो जाए, तो फिर किसी मनुष्य के लिए कार्य करना किस प्रकार संभव हो सकता है? पर जो अपने को सम्पूर्णतः भूल कर एकाग्रचित्त से कार्य करता है, उसका कार्य निश्चय ही अप्रतिम रूप से अच्छा होता है और इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में किया होगा। हम अनेक कार्य अचेतन होकर करते हैं, जैसे आहार को पचाना आदि, कुछ कार्य चेतन होकर करते हैं, तथा कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, जो मानो समाधि-अवस्था में मग्न होकर सम्पन्न होते हैं, जब हमें अपने क्षुद्र अहं का बोध नहीं रहता। यदि चित्रकार अपने को भूल कर चित्र बनाने में ही पूर्ण रूप से लीन हो जाए, तो उसका चित्र एक महान कृति होगा। एक अच्छा रसोइया भोजन बनाने के समय अपना सब कुछ उसमें लगा देता है; उस समय तक के लिए वह अन्य सब कुछ भूल जाता है। परंतु ये लोग इस प्रकार केवल उसी एक कार्य को अच्छी तरह से कर सकते, जिसके लिए वे अभ्यस्त होते हैं। गीता की शिक्षा है कि सभी कार्यों को इसी तरह पूर्णता के साथ करना चाहिए। जो योग के द्वारा प्रभु से एकरूप हो गया है, वह अपने सभी कार्यों को इसी एकाग्रता से करता है और अपने स्वार्थ की कुछ भी चाह नहीं रखता। इस प्रकार किए हुए कर्म द्वारा संसार की भलाई होती है, उससे किसी प्रकार की बुराई नहीं हो सकती। जो इस प्रकार कर्म करते हैं, वे अपने लिए कभी कुछ नहीं करते।

प्रत्येक कार्य का फल शुभ और अशुभ से युक्त रहता है। कोई भी शुभ काम ऐसा नहीं होता, जिसमें अशुभ का कुछ न कुछ स्पर्श न रहता हो। जैसे अग्नि धुएं से आवृत्त रहती है, उसी प्रकार कर्म में कोई न कोई दोष लगा ही रहता है। हमें ऐसे कार्यों में ही रत रहना चाहिए, जिनसे महत्तम शुभ और न्यूनतम अशुभ उत्पन्न हो। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण का वध किया। यदि न किया होता, तो दुर्योधन पर विजय प्राप्त न होती, अशुभ की शक्तियों की शुभ की शक्तियों पर विजय हो जाती; अभिमानी और अन्यायी राजाओं के एक दल के द्वारा राज्य का शासन बलपूर्वक हड़प लिया जाता और देश की जनता पर दुर्भाग्य की कालिमा फैल जाती। इसी प्रकार कृष्ण ने कंस इत्यादि अत्याचारियों का संहार किया, पर उनका एक भी कार्य उनके स्वयं के लिए नहीं था। उनका प्रत्येक कार्य दूसरों की भलाई के लिए ही था। हम दीपक के प्रकाश में गीता का पाठ कर रहे हैं, पर अनेक पतिंगे जल कर मरते जा रहे हैं। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक कर्म में कुछ कुछ दोष रहता ही है। जो अपना क्षुद्र अहंभाव भूल कर कार्य करते हैं, उन पर इन दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वे संसार की भलाई के लिए कर्म करते हैं। निष्काम और अनासक्त होकर कार्य करने से हमें परम आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्मयोग के इसी रहस्य की शिक्षा दी है।

**(स्वामी विवेकानंद ने 'निष्काम कर्म' पर यह भाषण रामकृष्ण मिशन की सभा में 20 मार्च, 1898 को दिया था।)**

**साभारः 'विवेकानंद साहित्य', रामकृष्ण मठ प्रकाशन**

बोध प्रसंग

# दोष नहीं, हमेशा गुण ढूंढें

**भगवान** श्रीकृष्ण सभी को समान रूप से प्रेम करते थे। वे कभी भी किसी का दोष नहीं देखते थे। उनका विचार था कि दूसरों के दोष देखने से मन मैला होता है। मैले मन से तो जीवन में शांति नही आ सकती, इसलिए दूसरों में दोष देखना एक विकार है।

एक बार नारदजी के मन में विचार आया कि श्रीकृष्ण के इस गुण की परीक्षा ली जाए। वे सुबह-सुबह द्वारिका के राजपथ पर एक रोगी और दुर्गंध फैलाने वाले श्वान के रूप में बैठ गए। कुछ देर बाद श्रीकृष्ण प्रातः भ्रमण हेतु निकले। आने-जाने वाले सभी लोग सोच रहे थे कि द्वारिकाधीश की दृष्टि जब इस श्वान पर पड़ेगी, तो आफत ही आ जाएगी, क्योंकि उन्हें सफाई अत्यंत पसंद है। प्रातः काल की शुद्ध वायु उसकी वजह से अस्वच्छ हो गई थी।

श्रीकृष्ण जैसे-जैसे उस श्वान के समीप आ रहे थे, सभी की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब वे उसके समीप आए, तो पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा- 'प्रभु, देखिए न इस अधम ने चारों ओर कैसी दुर्गंध फैला दी है। जरूर इसने पूर्व जन्म में कई पाप किए होंगे, इसलिए ईश्वर ने इसे कुछ भी अच्छा नहीं दिया।' तब श्रीकृष्ण मुस्कराकर बोले, 'नहीं, तुम गलत कह रहे हो, जरा ध्यान से देखो। इस श्वान के दांत कितने सफेद और चमकीले हैं। इसने पूर्वजन्म में अवश्य ही कोई पुण्य कर्म किया होगा, जिससे इसको इतने सुंदर दांत मिले हैं।'

श्रीकृष्ण का जवाब सुनकर नारद श्वान का शरीर छोड़कर प्रकट हुए और श्रीकृष्ण को अत्यंत भक्ति-भाव से प्रणाम किया। अब नारद जान गए थे कि एक बीमार श्वान में भी गुण खोज लेने की क्षमता ने ही श्रीकृष्ण को इतना बड़ा निष्काम कर्मयोगी बनाया है।

उनके इस भाव ने बताया कि आलोचना की दृष्टि डालेंगे, तो निंदा के बिंदु ही दिखेंगे। करुणा की दृष्टि होगी, तो अच्छे गुण दिखेंगे। निंदा करने वालों को शांति नहीं मिलती। हम सबके प्रति गुणग्राही दृष्टि रखें। इससे मन सदा शांत रहता है।

**राधा नाचीज**

आस्था स्थली: चिंतामण गणेश मंदिर, सीहोर, मध्य प्रदेश

# यहां स्वयं गणपति ने दी थी अपनी मूर्ति

देशभर में गणपति के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है सीहोर का चिंतामण गणेश मंदिर। कहते हैं यहां के गणेश जी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं, चिंता दूर करते हैं व मुरादें पूरी करते हैं। यह चिंतामण गणेश भारत में स्थित चार स्वयंभू मूर्तियों में से एक माने जाते हैं। सीहोर के गणपति के बारे में कहा जाता है कि भगवान गणपति आज भी यहां साक्षात मूर्ति रूप में निवास करते हैं। यह भी कहा जाता है कि बप्पा को यहां सच्चे मन से पूजने पर वे कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देते। इसी वजह से गणेश उत्सव के बाद भी यहां सालभर भक्तों का तांता लगा रहता है।

माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। प्रचलित कहानी के अनुसार महाराजा विक्रमादित्य को गणपति की यह मूर्ति स्वयं गणेश जी ने ही दी थी। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के पूजन से प्रसन्न होकर भगवान गणपति ने उन्हें दर्शन दिए और मूर्ति रूप में स्वयं ही यहां स्थापित हो गए और सदैव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया।

स्थानीय लोग बताते हैं कि जब भी महाराजा विक्रमादित्य संकट में होते थे या उन्हें कोई चिंता परेशान करती थी, तो वे गणपति बप्पा की शरण में यहां आया करते थे। इसके बाद उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। ऐसी मान्यता के चलते लोग यहां अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। वे बप्पा से अपनी चिंता दूर करने की मन्नत मांगते हैं।

यहां हर साल गणेश उत्सव के दौरान देशी और विदेशी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। गणेश चतुर्थी से शुरू होकर दस दिनों तक यहां विशाल मेला लगाता है। चिंतामण गणेश मंदिर दर्शन के लिए सुबह सूर्योदय से रात्रि नौ बजे तक खुला रहता है। प्रसाद के रूप में गणपति को यहां मोदक चढ़ाया जाता है। यहां दुकानदार विशाल आकार के मोदक बनाते हैं। आप सीहोर शहर में रुक कर भी दर्शन के लिए यहां पहुंच सकते हैं।

चिंतामण गणेश की चार प्रतिमाएं देशभर में मौजूद मानी जाती हैं। एक सवाई माधोपुर राजस्थान के रणथंभौर में, दूसरी उज्जैन में, तीसरी गुजरात के सिद्धपुर में और चौथी सीहोर में स्थित है।

**कैसे पहुंचें:** मंदिर तक सीहोर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से रिक्शा आदि वाहनों से पहुंच सकते हैं। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी तीन किलोमीटर है। भोपाल से सीहोर की दूरी 35 किलोमीटर है।

**अनादि अनंत**

# चिकन के बराबर पहुंची प्याज की कीमत, कोलकाता में 150 के करीब

**नई दिल्ली। एजेंसी**

देश के कई बड़े शहरों में प्याज की कीमत चिकन के बराबर पहुंचने वाली है। हालांकि इसकी कीमत जल्द ही 150 रुपये के पार जा सकती है, क्योंकि थोक कीमतें 135 रुपये हो चुकी हैं। वहीं ऑनलाइन ग्रॉसरी बेचने वाली कंपनियां प्याज को काफी सस्ती कीमतों पर बेच रही हैं। चिकन की कीमत बाजार में 160 रुपये के करीब है।

### उपभोक्ता मंत्रालय ने घटाई स्टॉक लिमिट

वहीं उपभोक्ता मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से प्याज बेचने वाले खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट को घटा दिया है। अब थोक व्यापारी 25 टन और खुदरा व्यापारी पांच टन से ज्यादा प्याज नहीं रख सकेंगे। हालांकि प्याज का आयात करने वालों पर किसी तरह की कोई सीमा लागू नहीं होगी।

### इन शहरों में भाव 130 रुपये

किलो देश के कई बड़े शहरों में प्याज की खुदरा कीमत 130 रुपये प्रति किलो के पार चली गई है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पुणे और ओडिशा में इस कीमत पर प्याज मिल रहा है। वहीं देश के अन्य शहरों में प्याज 90 से 100 रुपये प्रति किलो पर मिल रहा है।

### बिगड़ा रसोई का बजट

प्याज की कीमतों ने आम आदमी की रसोई के साथ ही छोटे-बड़े रेस्टोरेंट और होटल में भी असर देखने को मिला है। रेस्टोरेंट, ढाबों और ऑफिस कैंटीन में सलाद के तौर पर मूली-खीरा दिया जा रहा है। नासिक मंडी में प्याज का थोक भाव 135 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। कई जगह राज्य सरकारें और नेफेड, मदर डेयरी सफल जैसी संस्थाएं 24 से 60 रुपये किलो की कीमत पर प्याज बेच रहे हैं।

### ऑनलाइन 79 से 98 रुपये कीमत

ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म पर प्याज 79 रुपये से लेकर के 98 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज को बेच रही हैं। वहीं कुछ कंपनियां 246 रुपये में दो किलो आलू, एक किलो टमाटर और दो किलो प्याज बेच रही हैं।सरकार प्याज की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों में कमी लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। पिछले सप्ताह खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनी एमएमटीसी को एक लाख टन प्याज का आयात करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही भारत अब प्याज निर्यातक से आयातक बन गया है।

### क्यों बढ़े प्याज के दाम?

इस साल मई के बाद प्याज की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। बीते वर्ष प्याज का बहुत कम उत्पादन हुआ था। इसलिए इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बेमौसम बारिश की वजह से प्याज की फसल प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त कारोबारियों ने सरकार की प्रतिकूल नीतियों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। पहले लासलगांव की कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) के अध्यक्ष जयदत्त होल्कर ने कहा था कि अक्तूबर और नवंबर में बेमौसम वर्षा हुई है, जिसकी वजह से खरीफ में बोई गई फसलों को नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित दक्षिण भारतीय राज्यों में बोई गई शुरुआती किस्म की प्याज आवक को नुकसान पहुंचा है। यही कारण है, जिसकी वजह से बाजार में नई किस्म की प्याज आपूर्ति नहीं है। प्याज की सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र में होती है। भारत में प्याज के कुल उत्पादन का 35 फीसदी प्याज महाराष्ट्र से आता है। सितंबर माह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में हो रही बेमौसम बारिश से फसल को नुकसान पहुंचा है।

# ट्रक मालिकों को 31 दिसंबर तक मुफ्त फास्टैग उपलब्ध कराएगी ब्लैकबक

**नई दिल्ली।** ट्रांसपोर्ट कंपनियां और ट्रक चालकों को ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनी ब्लैकबक देशभर में ट्रक चालकों को 31 दिसंबर तक मुफ्त फास्टैग उपलब्ध कराएगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियां और ट्रक चालक कंपनी की ऐप से फास्टैग की बुकिंग कर सकते हैं, जिन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। सरकार ने देशभर के 500 से अधिक पथकर नाकों पर पथकर संग्रह के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान में सहायक फास्टैग लागू करने का यह फैसला नाकों पर

होने वाली भीड़भाड़ और देरी को खत्म करने के लिए किया गया है। पहले इसे लागू करने की अंतिम तिथि एक दिसंबर थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया है। कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसकी ऐप पर ट्रांसपोर्ट कंपनियां के फास्टैग के लिए आवेदन करने के बाद कंपनी चार से पांच दिनों के भीतर उनके पते पर यह फास्टैग पहुंचा देगी। इस पहल से भारत के 30 लाख से अधिक ट्रक मालिकों के लिए फास्टैग नियम का पालन करना आसान होगा। ट्रक मालिक इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लैकबक के सह-संस्थापक राजेश याबाजी ने बताया, 'फास्टैग को अनिवार्य करने के सरकार के इस निर्णय से डिजिटल मालवहन की अर्थव्यवस्था का सपना साकार होगा। 'फास्टैग ऐट डोरस्टेप' जैसी पहल से पहले ही 50 प्रतिशत भारतीय ट्रक कारोबारी ब्लैकबक मंच से जुड़ चुके हैं। हम सरकार के राष्ट्रीय पथकर एजेंडा को अपना समर्थन देने के लिए उत्साहित हैं। इससे पथकर नाकों पर लगने वाला समय बचेगा और भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी।'' मुफ्त फास्टैग उपलब्ध कराने के लिए कंपनी ने आईडीएफसी बैंक और यस बैंक के साथ साझेदारी की है।

# Maruti Suzuki की कारें हो रहीं महंगी

## जनवरी से बढ़ेगी कीमत

**नई दिल्ली। एजेंसी**

Maruti Suzuki की कारें महंगी होने वाली हैं। कंपनी ने मंगलवार को जानकारी दी कि वह जनवरी से अपनी कारों के दाम बढ़ाएगी। मारुति ने कहा है कि बढ़ती लागत की भरपाई के लिए वह कारों की कीमत में इजाफा कर रही है। मारुति सुजुकी का कहना है कि पिछले एक साल में विभिन्न इनपुट लागत में बढ़ोतरी के कारण कंपनी की गाड़ियों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मारुति सुजुकी ने कहा, 'कंपनी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह जनवरी 2020 से विभिन्न मॉडल्स की कीमत में बढ़ोतरी के माध्यम से अतिरिक्त लागत का कुछ भार ग्राहकों को दे।' कंपनी ने कहा है कि कीमतों में इजाफा विभिन्न मॉडल्स के लिए अलग-अलग होगा। मारुति के पोर्टफोलियो में कुल 16 गाड़ियां हैं। इनमें एंट्री लेवल ऑल्टो से लेकर प्रीमियम एमपीवी XL6 तक शामिल हैं। इन कारों की कीमत 2.89 लाख से 11.46 लाख रुपये के बीच है। ये कीमतें एक्स शोरूम दिल्ली की हैं।

### दो डीलरशिप से कारों की बिक्री

मारुति अपनी कारों को दो डीलरशिप- अरीना और नेक्सा से बेचती है। नेक्सा कंपनी की प्रीमियम डीलरशिप है, जिससे इग्निस, बलेनो, सियाज, एस-क्रॉस और एक्सएल6 बेची जाती हैं। वहीं, अरीना डीलरशिप से कंपनी ऑल्टो, ऑल्टो के10, सिलेरियो, सिलेरियो एक्स, वैगनआर, स्विफ्ट, डिजायर, एस-प्रेसो, ब्रेजा, अर्टिगा और ईको वैन बेचती है।

# शराब विनिर्माताओं की अति शुद्ध इथाइल एल्कोहल से आयात शुल्क हटाने की गुहार

**नयी दिल्ली।** भारतीय शराब विनिर्माताओं ने नीति आयोग से एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहॉल (ईएनए) यानी अति शुद्ध इथाइल एल्कोहल पर आयात शुल्क में छूट की मांग की है। ईएनए मुख्यतः एल्कोहल युक्त पेय सामग्री बनाने में इस्तेमाल होता है। विनिर्माताओं ने कहा कि तेल कंपनियों के ईंधन में इथाइल एल्कोहॉल मिलने के बाद से ईएनए की घरेलू आपूर्ति में भारी कमी आई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहॉलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) के महानिदेशक विनोद गिरि ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को लिखे पत्र में कहा , ' अति शुद्ध इथाइल एल्कोहल की उपलब्धता कम होने से एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ उद्योग के सामने अनिश्चितता की स्थिति खड़ी हो गई है। कुछ समय पहले थोक में इसका दाम 45 रुपये लीटर था , जो अब 60 रुपये लीटर के पार चला गया है।' सीआईएबीसी ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में आई बाढ़ से गन्ने की फसल प्रभावित हुई है , जिससे ईएनए की आपूर्ति की स्थिति और बिगड़ सकती है। घरेलू आपूर्ति सुधरने तक वाणिज्य मंत्रालय को अति शुद्ध एल्कोहल के आयात से शुल्क हटाने की सलाह दी जा सकती है। अति शुद्ध इथाइल एल्कोहल पर ज्यादा शुल्क अंतरराष्ट्रीय बाजार से आयात करने में बड़ी रुकावट है। विनिर्माताओं के संगठन ने कहा , ' अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईएनए के दाम 50 रुपये लीटर है। वर्तमान शुल्क (150 प्रतिशत) को जोड़ने पर यह 125 रुपये प्रति लीटर में पड़ता है , जो महंगा बैठता है। यदि इस पर आयात शुल्क हटा लिया जाए तो यह 50-55 रुपये में पड़ेगा। '

# आयकर विभाग ने जारी किए 2.10 करोड़ करदाताओं को 1.46 लाख करोड़ का रिफंड

**नई दिल्ली।** आयकर विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के शुरुआती आठ महीनों में करीब 2.10 करदाताओं को 1.46 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 20 फीसदी ज्यादा है। आयकर विभाग के केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच पिछले साल 1.75 करोड़ लोगों को 1.19 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया था। रिफंड की राशि भी पिछले साल के मुकाबले 22.7 फीसदी ज्यादा है। ज्यादातर करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खातों में इलेक्ट्रोनिक तरीके से ट्रांसफर किया गया। इससे चेक से राशि देने का दौर भी खत्म हो गया है। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान एक अप्रैल से लेकर 18 जून तक कुल 64,700 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया था। 2018-19 में करदाताओं को समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की याद दिलाने के लिए 26.9 करोड़ एसएमएस और ई-मेल भेजे गए। छोटे करदाताओं सहित सभी करदाताओं के लिए रिफंड जारी करना सरकार की पहली प्राथमिकताओं में शामिल है। 0.5 फीसदी से भी कम आईटीआर को जांच के लिए चुना गया है। अधिकांश रिटर्न पर तेजी से कार्रवाई की गई है और रिफंड जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से आईटीआर की प्रक्रिया पूरी करने में लगने वाला समय लगातार कम हो रहा है।

# केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को मंजूरी दी

**नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी । केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी । इस विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि यह विधेयक संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जायेगा । समझा जाता है कि विधेयक में निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के मॉडल का भी उल्लेख होगा । पिछले सप्ताह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार जल्द ही संसद में निजी डेटा के संरक्षण के बारे में एक संतुलित विधेयक पेश करेगी ।

www.eng-expo.co.in
www.eng-expo.in

## Why Should You
### Participate in Madhya Pradesh ?

- Explore the unexplored opportunities.
- Biggest automobile hub in India.
- Most flourishing food and grain industry.
- Industrial Development on a rapid pace in Plastic Parks, Textile Parks, SEZs, Pharma Zones.
- Both IIMs and IITs are here
- Cleanest city of India third time in a row (IT'S A HATTRICK).
- Fast infrastructure development.
- Centrally connected transport system.
- Good, peaceful and conducive atmosphere for business development.
- Well equipped communication network.
- Proactive initiatives by the state government.

Central India's Largest SME Exhibition

# Industrial ENGINEERING EXPO

CONCURRENT EVENTS

3rd International Industry & Technology Expo

PLAST PACK & PRINT EXPO 2019

ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2019

INDORE 20 21 22 23 DEC 2019

LABHGANGA EXHIBITION CENTRE

SPONSORED BY

CO-SPONSORED BY

ORGANISED BY

CONCURRENT EVENT ORGANISED BY

SPONSORED BY

SUPPORTED BY

For Participation Call

9826887800, 9826497000, 9981224262, 9827044408

futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।